Title: Raised a matter pertaining to not issuing the vehicle-permit by the Transport Department to Scheduled Tribes of Madhya Pradesh.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त विकास निगम का गठन किया गया है और निगम में आदिवासियों की सुख-सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए अनेक योजनायें बनाई गयी हैं। परन्तु वर्तमान समय में १९९६ से लेकर आज तक अनेक ऐसी योजनाओं का लाभ आदिवासियों को मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो नीतिसंगत विषय बनाया है, उस नीति के अनुरूप कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया है कि पिछले समय रायपुर निवासी अशोक कुमार नाम के व्यक्ति को एक बस दी गई थी परन्तु उसको अभी तक परमिट नहीं दिया गया। इसी तरह जिन आदिवासियों को बस के लिए ऋण दिया गया है, उनसे ६ परसेंट ब्याज लेना था परन्तु मध्य प्रदेश सरकार और कार्पोरेशन उनसे १२ परसेंट से लेकर १४ परसेंट तक ब्याज वसूल कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर अपराध है। इसी प्रकार इस वित्त विकास निगम के माध्यम से हजारों आदिवासियों को भारत सरकार की तरफ से टाटा कम्पनी की गाड़ियां देनी थीं परन्तु उनको टाटा कम्पनी की गाड़ियां न देकर स्वराज माजदा कम्पनी की गाड़ियां दी गयी। ऐसी अनेक घटनायें सामने आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें १५ करोड़ रुपये के ऐसे मामले सामने आये हैं। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं और आपकी अनुमति से भारत सरकार से इस पर कठोर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन आदिवासियों को वह सुख-सुविधा मिलनी चाहिए थी, उनको वह नहीं दी गयी। अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति को परमिट नहीं दिया गया। उसको कमिश्नरी के सामने अपने आप आत्महत्या करनी पड़ी। यह गंभीर अपराध है। वित्त विकास निगम के अध्यक्ष ने भी वहां के एम.डी. पर चार्ज लगाया कि एम.डी. के रहते हुए और इस विभाग के मिनिस्टर के संरक्षण में जिन लोगों को सुविधायें मिलनी चाहिए थीं, जो आवंटन देने थे, उन आवंटनों का लाभ आदिवासियों को न मिलकर बड़े-बड़े लोगों को मिला।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर गंभीरता से चिन्ता करे चूंकि यह सम्पूर्ण मामला मध्य प्रदेश के आदिवासियों का है। मैं यह भी मांग करता हूं कि भारत सरकार इस मामले की तुरन्त जांच कराये। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। ... (व्यवधान) हम चाहते हैं कि आप इसके लिए एक जांच कमेटी बैठायें।

... (व्यवधान)

मंत्री जी इसके बारे में कुछ कहें।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Would the Government like to respond?

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : अध्यक्ष महोदय, यह आर्थिक अपराध का मामला है।

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है।

... (व्यवधान)

... (Interruptions)

MR. SPEAKER : Please take your seat. Is there any response from the Government side?

... (Interruptions)

श्री रामानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसपर सरकार की ओर से कोई जवाब तो आना चाहिए। सरकार क्या कहना चाहती है?

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please take your seat. I am asking the Government to respond to it. Is there any response from the Government side? They are raising a matter regarding a specific programme with regard to the State of Madhya Pradesh. Hon. Minister, please make a note of it.

... (Interruptions)

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर): मंत्री जी को विषय की जानकारी नहीं मिली है तो मैं फिर से मंत्री जी को बता देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों को आदिवासी वित्त निगम के माध्यम से वाहन सुविधा उपलब्ध कराई थी, किन्तु परिवहन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि जो सुविधा आदिवासियों को दी जा रही थी, वे उसके लिए परमिट नहीं देते। परमिट नहीं देने के कारण जो वाहन की सुविधा दी जा रही है, उसका उपयोग नहीं हो रहा। जो वाहन आदिवासियों ने लिये हैं, वे परमिट के अभाव में घर पर खड़े हुए हैं।

MR. SPEAKER : Hon. Minister, please make a note of it.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER : Please take your seats. I am asking the Government to respond to it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): Mr. Speaker, Sir, I think, the subject belongs to the domain of the State Government. But even then, since it is pertaining to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, - if the facts stated by the hon. Members are correct, then it is a matter of concern - the Central Government will take it up with the State Government.

MR. SPEAKER : All right. Now, Shri Ram Nagina Mishra.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER : Please take your seats. Hon. Minister has already replied to it. Please take your seats.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER : It will not go on record. Shri Ram Nagina Mishra's speech only will go on record.